(घ) औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1982=100) के अनुसार भारतीय रुपए की क्रय शक्ति का आकलन दिसम्बर, 1992 के 41.15 पैसे के मुकाबले दिसम्बर, 1993 में 37.38 पैसे था।

Strike by Bank Employees

*94. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Hindustan Times dated the 18th February, 1994 captioned "Bank Staff strike near total" all over the country, on 17th February 1994 including RBI and reported statement of the General Secretary of Bank Employees Federation of India saying that the strike was a warning to Government that the ill-conceived policies at the dictates of IMF and World Bank will not be tolerated by bankmen and the country's people;

(b) what were the main demands, reasons which led to strike and suspension of clearing house operations in the country;

(c) what steps Government propose to take to meet their demands, particularly immediate holding of meaningful wage negotiations, as the last charter was valid only upto November, 1992; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The one-day strike on 17.2.94 in some of the banks was to protest primarily against alleged privatisation of banks, closure of branches, job security, early wage revision, and introduction in Parliament of the Bill enabling nationalised banks to raise share capital from the public. Government have, on a number of occasions, allayed the fears of bankmen and have reiterated there was no intention to denationalise public sector banks or to undertake any retrenchment of staff. At the same time, it has been emphasised that there is an urgent need to improve efficiency so as to meet the requirements of a competitive economy.

In relation to the demand for wage revision, several rounds of discussions on the charter of demands submitted by the employees' unions for the 6th Bipartite Settlement have so far taken place between IBA and representatives of employees' unions and in pursuance of these discussions, memoranda of understanding have already been signed between the maior employees unions and the IBA with regard to pension in lieu of CPF and on computerisation and mechanisation. Further discussions between IBA and the employees' representatives are going on.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सौदे

*95. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:**
श्री ओ० राजगोपाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सौदों में कमीशन के लिए जाने को वैधता प्रदान की है;

(ख) क्या इन नियमों में विगत सात वर्षों में कोई अपवाद भी रहे हैं; और

(ग) विवादास्पद सौदे के मामले में उससे निपटने के लिए क्या कोई पंचाट व्यवस्था उपलब्ध है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कुल्लू-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर केबल फाइबर का बिछाया जाना

*96. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संचार विभाग द्वारा अपने ठेकेदारों की मार्फत "कुल्लु-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग" पर केबल फाइबर बिछाने हेतु खुदाई का काम समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त काम को अव्यवस्थित रूप से किये जाने के फलस्वरूप जनसाधारण का चलना और वाहनों का आना-जाना खतरे से खाली नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त कारण से इस राजमार्ग पर अनेक छुट-पुट दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और गत दो महीनों में इन खाइयों में गिरने से दो व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो विभाग द्वारा इन असुविधाओं को दूर करने और वहां ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, नहीं। ठेकेदारों द्वारा कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। जैसा कि देश के अन्य भागों में किया जा रहा है, कुल्लू-मंडी खण्ड में भी आप्टिकल फाइबर केबल ठेकेदारों के माध्यम से बिछाये जा रहे हैं।

(ख) जी हां। दुर्गम भू-भाग होने और इस क्षेत्र की सड़कें तंग होने के कारण तथा आप्टिकल फाइबर की सुरक्षा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, कार्य सुव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। तथापि, सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सावधानी बरतना अनिवार्य हो गया है।

(ग) जी हां। अब तक न तो कोई ऐसा दृष्टान्त हमारे ध्यान में आया है और न ही राज्य सरकार से इस संबंध में कोई शिकायत हमें प्राप्त हुई है।

(घ) हिमाचल प्रदेश की, विशेषकर कुल्लू-मण्डी खण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य पर एक सहायक इंजीनियर के नेतृत्व में कर्मचारियों के एक दल द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा चेतावनी की घडियां, चेतावनी बत्तियां और सावधान रहने के अनुदेशों वाले बोर्ड भी लगाये जाते हैं। यह कार्य मार्च, 1994 तक पूरा होने की संभावना है।

**97. [Transferred to 4th March 94].*

Foreign Exchange Earnings from Private Airlines

*98. SHRI M.A. BABY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the foreign exchange earnings made through each private airlines in India for the last twelve months; and

(b) the foreign exchange outflow of each private airlines in India for the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Credit Delivery System in Rural Sector

*99. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the RBI has decided to modify the credit delivery system in the rural sector by providing a greater role to non-Government Organisations and self-help groups; and

(b) if so, what are the precise changes effected in this regard and what difficulties and shortcomings are proposed to be overcome thereby?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS) DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Reserve Bank of India (RBI) have reported that there is no proposal to modify the credit delivery system in rural sector. Banks continue to finance borrowers directly as hitherto. However, with a view to improving access of the poor to bank credit, it has been considered advantageous to link the rural